



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]

नई दिल्ली, मंगलवार, 28 अगस्त 2001/भाद्र 6, 1923

No. 233]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 28, 2001/BHADRA 6, 1923



वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2001

विषय : यू. के., जर्मनी, ब्राजील और बुलगारिया से भारत में एक्रीलिक फाइबर के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना।

सं. 42/1/2001-डीजीएडी.—एक्रीलिक फाइबर्स विनिर्माता फोरम, नई दिल्ली ने सहयोगी कंपनियों, अर्थात् मैसर्स इंडियन एक्रीलिक्स लि., चंडीगढ़, मैसर्स कंसोलिडेटेड फाइबर्स और कैमिकल्स लि., कलकत्ता, मैसर्स पशुपति एक्रीलोन लि., नई दिल्ली के जरिए 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है, जिसमें यू. के., जर्मनी, ब्राजील और बुलगारिया मूल के या वहाँ से निर्यातित एक्रीलिक फाइबर के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है। दो अन्य घरेलू उत्पादकों, अर्थात् मैसर्स इंडियन पेट्रोकैमिकल्स एंड कैमिकल्स लि., बड़ौदा, और मैसर्स वर्धमान एक्रीलिक्स लि., लुधियाना ने इस याचिका का समर्थन किया है।

शामिल उत्पाद

2. वर्तमान याचिका में शामिल उत्पाद एक्रीलिक फाइबर (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) है। एक्रीलिक फाइबर सिथेटिक पोलीमर की एक लंबी शृंखला होती है, जिसमें भार के अनुसार एक्रीलोनाइट्राइल यूनिटों का कम से कम 90% होता है। एक्रीलिक फाइबर, एक्रीलिक स्टेपल फाइबर, एक्रीलिक टो या एक्रीलिक टॉप हो सकता है। एक्रीलिक फाइबर का इस्तेमाल मानव जीवन के दैनिन्दिन उपयोग जैसे परिधान, घरेलू औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि एक्रीलिक फाइबर सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण के अध्याय 55 मुख्य शीर्ष 5501 और 5503 और इनसे संबंधित छः अंकीय वर्गीकरण 5501.30 तथा 5503.30 के तहत वर्गीकृत हैं। तथापि, ये सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं। और वर्तमान जांच के कार्य क्षेत्र में किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं हैं।

घरेलू उद्योग

यह याचिका सहयोगी कंपनियों, अर्थात् मैसर्स इंडियन एक्रीलिक्स लि., चंडीगढ़, मैसर्स कंसोलिडेटेड फाइबर एंड कैमिकल्स लि., कलकत्ता, मैसर्स पशुपति एक्रीलोन लि., नई दिल्ली के जरिए एक्रीलिक फाइबर विनिर्माता फोरम, नई दिल्ली द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का एक्रीलिक फाइबर के कुल घरेलू उत्पादन में 50% से ज्यादा हिस्सा बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता उपरोक्त नियमों के नियम 5(3)(क) के अनुसार याचिका दायर करने के आधार संबंधी मापदंडों को पूरा करते हैं। दो अन्य घरेलू उत्पादकों अर्थात् मैसर्स इंडियन पैट्रोकैमिकल्स एंड कैमिकल्स लि., बड़ौदा और मैसर्स वर्धमान एक्रीलिक्स लि., लुधियाना ने इस याचिका का समर्थन किया है।

शामिल देश

4. वर्तमान जांच में शामिल देश यू.के., जर्मनी, ब्राजील और बुलगारिया (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) हैं।

समान वस्तु

5. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु यू.के., जर्मनी, ब्राजील और बुलगारिया में उत्पादित वहां के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित वस्तु को उपरोक्त नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

सामान्य मूल्य

6. याचिकाकर्ताओं ने यू.के. में हुई घरेलू बिक्रियों के साक्ष्य के आधार पर यू.के. से किए गए निर्यातों के संबंध में सामान्य मूल्य का दावा किया है। जर्मनी से हुए निर्यातों के संबंध में सामान्य मूल्य का दावा जर्मनी से तीसरे देश को हुए निर्यातों के साक्ष्य के आधार पर किया गया है। ब्राजील और बुलगारिया से हुए निर्यातों के संबंध में सामान्य मूल्य का दावा प्रशासनिक, बिक्री लागत और लाभों के लिए समुचित अभिवृद्धि के साथ संबद्ध वस्तु के उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर किया गया है। ब्राजील और बुलगारिया के संबंध में उत्पादन की परिकलित लागत निकालने के लिए एक प्रमुख कच्ची सामग्री एक्रीलोनाइट्राइल की कीमत के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।

निर्यात कीमत

7. याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देशों से एक्रीलिक फाइबर के आयातों के संबंध में डी जी सी आइ एंड एम द्वारा प्रकाशित आकड़ों को प्रस्तुत किया है। कारखाना द्वारा पर निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन, स्वदेशी परिवहन और पत्तन हैंडलिंग प्रभारों इत्यादि के लिए समायोजनों का दावा किया है।

पाटन मार्जिन

8. इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

9. क्षति से संबंधित विभिन्न सकेतकों जैसे बाजार हिस्से में कमी, बिक्री में कमी, संबद्ध वस्तु की बिक्री से उचित कीमत प्राप्ति में असमर्थता की वजह से घरेलू उद्योग की बिक्री प्राप्ति, लाभ प्रदत्ता में कमी से समग्र तथा संचयी रूप से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

पाटनरोधी जांच की शुरूआत

10. उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आरोपित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं।

जांच की अवधि

11. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च 2001 तक की है।

सूचना देना

12. संबद्ध देश में निर्यातकों और भारत में आयातकों, जिन्हें संबंधित समझा जाता है, को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबंध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011 को निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से संबंधित सूचना भेजें तथा अपने विचारों से अवगत कराएं कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है।

समय सीमा:

13. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत करनी होगी।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

14. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समयावधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं करती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

एल. थी. सप्तश्चिति, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2001

Subject : Initiation of Anti-dumping investigation concerning import of Acrylic Fibre from UK, Germany, Brazil and Bulgaria into India.

No. 42/1/2001-DGAD.—Forum of Acrylic Fibres Manufacturers, New Delhi through the participating companies, viz., M/s. Indian Acrylics Ltd., Chandigarh, M/s. Consolidated Fibres and Chemicals Ltd., Calcutta, M/s. Pasupati Acrylon Ltd., New Delhi; have filed a petition in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Acrylic Fibre originating in or exported from UK, Germany, Brazil and Bulgaria and requested for Anti Dumping investigations and levy of anti dumping duties. Two other domestic producers, viz., M/s. Indian Petrochemicals and Chemicals Ltd., Baroda, and M/s. Vardhman Acrylics Ltd., Ludhiana have supported the petition.

PRODUCT INVOLVED

2. The product involved in the present petition is Acrylic Fibre in all Deniers (hereinafter referred as subject goods). Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile units. Acrylic Fibre can be Acrylic staple fibre, acrylic tow or acrylic top. Petitioners have claimed that Acrylic Fibre is classified under Chapter 55 of Customs Tariff Classification Major Heads 5501 and 5503 with respective six digit classification 5501.30 and 5503.30. These Custom classifications are however, indicative only and are in no way binding on the scope of the present investigation.

DOMESTIC INDUSTRY

3. The petition has been filed by Forum of Acrylic Fibres Manufacturers, New Delhi through the participating companies, viz., M/s. Indian Acrylics Ltd., Chandigarh, M/s. Consolidated Fibres and Chemicals Ltd., Calcutta, M/s. Pasupati Acrylon Ltd., New Delhi. The petitioners' share in the total domestic production of Acrylic Fibre is more than 50% and therefore, the petitioners satisfy the criteria of standing to file the petition in terms of Rule 5(3) (a) of the Rules supra. Two other domestic producers, viz., M/s. Indian Petrochemicals and Chemicals Ltd., Baroda; and M/s. Vardhman Acrylics Ltd., Ludhiana have supported the petition.

2690 61/2001-2

COUNTRIES INVOLVED

4. The countries involved in the present investigation are UK, Germany, Brazil and Bulgaria (hereinafter referred to as the subject countries).

LIKE ARTICLE

5. The petitioners have claimed that the goods produced by them are like articles to the goods produced, originating in or exported from UK, Germany, Brazil and Bulgaria. Therefore, for the purpose of the present investigation, the goods produced by the petitioners are being treated as 'like articles' to that imported from the subject countries within the meaning of the Rules supra.

NORMAL VALUE

6. The petitioners have claimed Normal Value in respect of exports from UK on the basis of evidence of domestic sales in UK. Normal value in respect of exports from Germany has been claimed on the basis of evidence of exports from Germany to an appropriate third country. Normal value in respect of exports from Brazil and Bulgaria has been claimed on constructed cost of production of the subject goods with reasonable addition for administrative, selling cost and for profits. Evidence has been furnished in respect of the price of a major raw material Acrylonitrile for arriving at the constructed cost of production in respect of Brazil and Bulgaria.

EXPORT PRICE

7. The petitioners have furnished the data published by the DGCI&S regarding imports of Acrylic Fibre from subject countries to determine the export price of the subject goods. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, insurance, commission, inland transportation and port handling charges to arrive at the Export Price at ex-factory level.

DUMPING MARGIN

8. There is sufficient evidence that Normal Value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the net export price indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by exporters from the subject countries.

INJURY AND CAUSAL LINK

9. Various parameters relating to injury such as the decline in market share, decline in sales, decline in the sales realisation, profitability of the Domestic Industry due to inability to realize fair and reasonable price from sale of the subject goods, prima-facie indicate collectively and cumulatively that the Domestic Industry has suffered material injury on account of dumping.

INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATIONS

10. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

11. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April 2000 to 31st March 2001.

SUBMISSION OF INFORMATION

12. The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

TIME LIMIT

13. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however, required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

14. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

